>

Title: Need to give special packages to backward states in the country.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सदन में वित्त मंत्री जी ने पिछड़े राज्यों को मदद देने के लिए जो रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। उसके बाद वित्त मंत्री जी जवाब देकर, सिर झुका कर चले गए। ऐसा लगा कि वे सदन को और हम लोगों को फेस नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक्टिव कंसीडे्रशन में है, उस समिति पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 26 नवम्बर को वित्त मंत्रालय में एक बैठक आयोजित थी। मेरा इस सरकार पर सीधा आरोप है कि राजनीतिक कारणों से वित्त मंत्रालय की 26 नवम्बर की वह बैठक स्थगित कर दी गयी। जिस सरकार की यह नीयत हो कि वह राजनीतिक कारणों से राज्यों के पिछड़ापन को दूर करने का निर्णय ले, उस सरकार से कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार का यह दावा खोखला है कि वह इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वास्तव में, वे पिछड़े राज्यों को और पीछे ढकेलना चाहते हैं।

कल मैंने देखा कि यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री से मिलीं और उन्होंने कहा कि सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्ज़ा मिलना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। सीमांध्र को भी विशेष राज्य का दर्ज़ा मिले। हम उसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन रघुराम राजन कमेटी ने जिन राज्यों के बारे में साफ तौर पर लिखा है कि ये राज्य पिछड़े नहीं, अति पिछड़े हैं, उनके बारे में अंतिम निर्णय क्यों रोका गया, इसका जवाब इस सरकार को जनता के सामने देना चाहिए। उसमें कई पिछड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भी है। उसमें बिहार है। उसमें उड़ीसा है। उसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। अगर यहां की प्रति व्यक्ति आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, प्रति व्यक्ति के खर्च को नहीं बढ़ाया जाएगा तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

हमारा आरोप है, सीधा आरोप है कि इस कारण से वित्त मंत्री जी बिना नज़र मिलाए हुए चले गए। उनके मन में खोट था, इसलिए 26 नवम्बर की बैठक रद्द हुई और यह सीधा आरोप लगाते हुए और इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए, इस सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं।

16.33 hrs.

Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh and some other hon. Members then left the House